कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

आवरण कथा

प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक बांग्लादेश दौरा........ 16

संगठनात्मक गतिविधियां : सदस्यता अभियान

जन कल्याण पर्व : रैलियां

करनाल (हरियाणा)........ 13

पणजी (गोवा)........ 13

सूरत (गुजरात)........ 14

सरकार की उपलब्धियां

'डीडी किसान' चैनल का उद्घाटन........ 6

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ पार........ 15

उत्तर-पूर्व क्षेत्र मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में........ 30

विशेष साक्षात्कार

श्री भूपेन्द्र यादव, राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा........ 23

श्रद्धांजलि : 23 जून बलिदान दिवस पर विशेष

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी : एक आदर्श नेता........ 26

अन्य

मन की बात........ 28

21 जून : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस........ 29

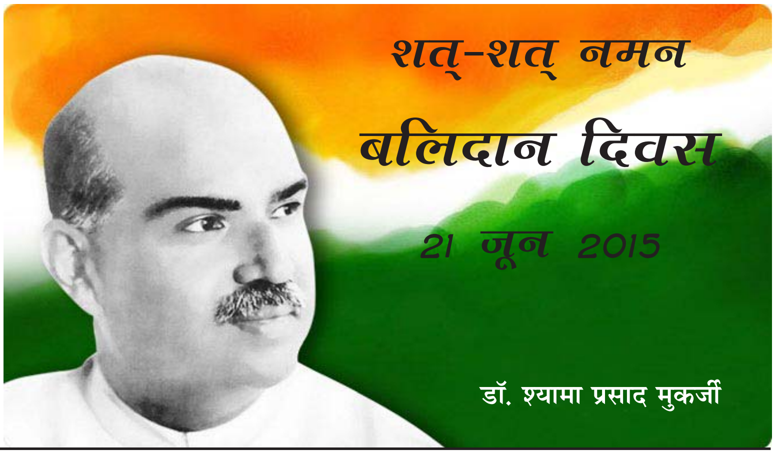

बोध कथा

स्वराज का अधिकार

यह घटना उस समय की है जब देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन जोर पकड़ रहा था। अनेक युवा अपना सर्वस्व समर्पण करने को तैयार थे। उधर अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में फंसे हुए थे। मुंबई के गवर्नर लार्ड विलिंग्डन ने इस जंग में भारतीयों की सहायता लेने के लिए 'युद्ध परिषद' का आयोजन किया। उसमें अनेक भारतीय नेताओं के साथ बाल गंगाधर तिलक को भी आमंत्रित किया गया। कई भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों को आश्वासन दिया कि वे विश्वयुद्ध में अंग्रेजों को हर संभव सहयोग देंगे।

अनेक नेताओं की बात सुनकर उन्हें पूरी आशा थी कि तिलक भी यही कहेंगे। उन्होंने उन्हें मंच पर आमंत्रित किया। जैसे ही तिलक मंच पर आए वे बोले, 'किसी भी बाहरी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए हम भारतीय सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे, किंतु स्वराज और स्वदेश रक्षा के प्रश्न पर सरकार को स्पष्ट वचन देना होगा।' 'स्वराज' शब्द सुनते ही विलिंग्डन का चेहरा तमतमा उठा। वह अपने स्थान से उठे और बोले, 'यहां राजनीतिक चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप हमारी सहायता का आश्वासन दीजिए और बोलिए कि आप हमारे साथ हैं।'

यह सुनकर तिलक बोले, 'गवर्नर साहब, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यदि आप इस शब्द को सुनने के लिए तैयार नहीं, तो मुझ जैसा भारतीय यहां एक क्षण भी नहीं रुक सकता।' यह सुनकर विलिंग्डन दंग रह गए। वे बोले, 'क्या हर समय तुम्हारे दिमाग में स्वराज गूंजता रहता है?' तिलक बोले, 'बिल्कुल और यह शब्द तब तक मेरे दिमाग में गूंजता रहेगा जब तक कि मेरे देश को पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता।' इस घटना में तिलक के द्वारा कही गई बात 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' एक प्रसिद्ध नारा बन गया।

संकलन : रेनू सैनी

(नवभारत टाइम्स से साभार)

पाथेय

आर्थिक प्रजातंत्र

भारतीय चेतना प्रकृति से प्रजातंत्रीय है और आज का युग भी प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा है। राजनीति के क्षेत्रों में यह प्रजातंत्र का भाव बहुत कुछ स्पष्ट होकर आया है तथा अब आर्थिक क्षेत्र में भी इसी प्रजातंत्र का उदय हो रहा है। राजनीतिक शक्ति का प्रजा में विकेंद्रीकरण करके जिस प्रकार शासन की संस्था का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार आर्थिक शक्ति का भी प्रजा में विकेंद्रीकरण करके अर्थव्यवस्था का निर्माण और संचालन होना चाहिए। राजनीतिक प्रजातंत्र में व्यक्ति की अपनी रचनात्मक क्षमता को व्यक्त होने का पूरा अवसर मिलता है। ठीक इसी प्रकार आर्थिक प्रजातंत्र में भी व्यक्ति की क्षमता को कुचलकर रख देने का नहीं अपितु उसको व्यक्त होने का पूरा अवसर प्रत्येक अवस्था में मिलना चाहिए।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

सम्पादकीय

बुरे दिन बीत गये – अब सुनहरे भविष्य की तैयारी!

भाजपानीत राजग सरकार के एक वर्ष पूरे होने का पूरे देश में जबरदस्त उत्साह एवं आशा के साथ स्वागत हुआ है। यह एक ऐसा भी अवसर है जब पीछे मुड़कर कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के घोर निराशापूर्ण दिनों की तुलना में एक वर्ष में अर्जित उपलब्धियों को उनके संदर्भों में समझा जाये। कोई भी विवेकपूर्ण मूल्यांकन इस बात से सहमत होगा कि देश को न केवल दुर्दिन से उबारा गया है, बल्कि सुशासन एवं विकास के राह पर ला खड़ा किया गया है। इस बात पर सब एकमत हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ऊर्जावान एवं दूरदृष्टि वाले नेतृत्व में देश सही दिशा में तेजी से बढ़ चला है। हर ओर उपलब्धियां, अनूठी पहल, अभिनव कार्यक्रम, सटीक कार्यान्वयन, भविष्योन्मुखी योजनाएं, दृढ़निश्चयी नेतृत्व और समर्पित तंत्र का बोलबाला है। राजनीति की परिभाषा, सुशासन का अर्थ और पूरी कार्य-संस्कृति सकारात्मक परिवर्तनों से लबालब भरा हुआ है। हमें देश को आगे ले जाना है, हमें नया भारत बनाना है- यह उद्‌गार अब हर कंठ से निकल रहा है।

लूट एवं भ्रष्टाचार का युग अब समाप्त हो चुका है। हर दिन घोटालों एवं घपलों को समर्पित कांग्रेसनीत संप्रग सरकार का दौर अब बीत चुका है- सरकार अब भ्रष्टाचार एवं लूट के पर्याय के रूप में नहीं जानी जाती। यह ऐसी सरकार है जो पारदर्शी एवं जवाबदेह है। कोयला घोटाला एवं स्पैक्ट्रम नीलामी में लूट का अध्याय बंद कर मोदी सरकार ने यह दिखा दिया है कि पारदर्शिता एवं शुचितापूर्वक काम कर कैसे सरकार की तिजोरी भरी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि बिचौलियों एवं दलालों के लिए अच्छे दिन नहीं हैं। 'प्रधान संतरी' के रूप में उन्होंने अवैध तरीके से जनता के पैसे की लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सरकार ने न केवल लूट-खसोट एवं भ्रष्टाचार के राज का खात्मा किया है, बल्कि तकनीक के उपयोग से यह भी सुनिश्चित किया है कि पूरी व्यवस्था जनता के हित में सुगठित हो। बड़ी संख्या में अनावश्यक कानूनों को निरस्त कर व्यवस्था पर लदे हुए अनचाहे बोझ को खत्म किया गया है। पूरी व्यवस्था को अवरोधमुक्त, चुस्त-दुरूस्त एवं गतिशील बनाकर शासन को भागीदारीपूर्ण बनाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ढालने के सार्थक प्रयास हो रहे हैं।

भाजपानीत राजग सरकार ने अपने पहले ही मंत्रीमंडल बैठक में काले धन पर एसआईटी गठित कर अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी कांग्रेसनीत संप्रग सरकार काले धन पर एसआईटी गठित करने से कतराती रही, मोदी सरकार ने अपने पहले ही निर्णय में एसआईटी गठित कर भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश दिया। इतना ही नहीं काले धन पर कठोर कानून भी बनाये गये। प्रधानमंत्री ने जी-20 शिखर सम्मेलन तथा स्विट्‌जरलैण्ड सहित अन्य देशों के साथ नये समझौते कर काले धन के मुद्दे को विश्व पटल पर मजबूती से रखा। हर क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप आर्थिक परिदृश्य में व्यापक सुधार के साथ-साथ भारत विश्व में सबसे तेजी से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए 'मेक इन इण्डिया' के तहत निवेश के लिये बड़े अवसर के रूप में उभरी है। आर्थिक क्षेत्र में अद्‌भुत उपलब्धियों से जहां भारत की रेटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधरी है, वहीं 'स्किल-इण्डिया' से युवाओं को 'मेक-इन-इण्डिया' से उपलब्ध होने वाली जबरदस्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार किया जा रहा है। विश्व में हर ओर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है और वे अपने दृष्टि एवं नेतृत्व के लिए सराहे जा रहे हैं।

गत एक वर्ष में भारत ने विश्व-पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। भारत में लोग

अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो रहे हैं। भारत को एक विकसित एवं स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। कृषि से लेकर उद्योग तथा आंतरिक से लेकर विदेश नीति तक व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है।

पूरा देश एक नई ऊर्जा एवं उत्साह से ओत-प्रोत है। अपेक्षाएं आसमान छू रही हैं, सपनों को पंख मिल चुके हैं और लोग महसूस कर रहे हैं कि वे सुनहरे भविष्य को यथार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। नीति-पंगुता, घोटाले, घपले एवं भ्रष्टाचार के दिन लद चुके हैं। लोकहितकारी व्यवस्था लोगों की भागीदारी से गरीबों-वंचितों के लिए प्रतिबद्धता के लिए अब तत्पर हैं।

भारत को नरेन्द्र मोदी में एक नया नेतृत्व, भाजपा में भारत निर्माण का एक आंदोलन एवं स्वयं में विश्वास करने का माद्दा मिल चुका है। गत एक वर्ष ने विश्व को यह दिखा दिया है- हां, हम कर सकते हैं।

अब भारत इस संकल्प के साथ उठ खड़ा हो चुका है- हां, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। ■

'डीडी किसान' चैनल का उद्‌घाटन

तहसील कृषि विकास की इकाई होनी चाहिए : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खाद्यान्न की उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर 2 टन से बढ़ाकर 3 टन करने की जरूरत को रेखांकित किया। गत 26 मई को विशेष रूप से किसानों को समर्पित दूरदर्शन के चैनेल 'डीडी किसान' की लांचिंग के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 'तहसील' को कृषि नियोजन एवं

विकास की इकाई बनाने पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश को आगे ले जाना है तो गांवों में तरक्की सुनिश्चित करनी होगी और अगर गांवों में तरक्की सुनिश्चित करनी है तो ऐसे में कृषि क्षेत्र का विकास निहायत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक समय कृषि सबसे पसंदीदा पेशा थी, लेकिन आगे चलकर इसका आकर्षण घटकर तलहटी पर आ गया। उन्होंने यह भी कहा कि उपर्युक्त प्रोत्साहन देकर और समुचित कदम उठाकर इस रुख को पूरी तरह पलटा जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा का स्मरण किया, जिसने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को तहेदिल से प्रेरित कर दिया था। उन्होंने कहा कि उसी प्रेरणा और जज्बे की फिर से जरूरत है, ताकि देश दालों एवं तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डीडी किसान चैनल को हमेशा सजग रहते हुए मौसम, वैश्विक बाजारों इत्यादि में होने वाले बदलावों से किसानों को अवगत कराते रहना चाहिए, ताकि किसान पहले से ही उपयुक्त योजनाएं बना सकें और समय पर सही निर्णय ले सकें।

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण युवाओं को बड़े पैमाने पर कृषि से पुनः जोड़ने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि डीडी किसान चैनल प्रगतिशील किसानों के प्रयासों को सभी लोगों के सामने लाने का काम भी कर सकता है, ताकि उनके अभिनव कदमों को देश भर में आजमाया जा सके। प्रधानमंत्री ने किसानों से कृषि क्षेत्र के लिए त्रिआयामी अवधारणा अपनाने को कहा जिनमें संतुलित खेती, पशुपालन और वृक्षारोपण शामिल हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह और केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौर इस अवसर पर उपस्थित थे। ■

जन-कल्याण सभा : मथुरा

बुरे दिन बीत गए : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की पहली सालगिरह की पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान में आयोजित जन कल्याण रैली को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में एनडीए सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है, विकास की गति तेज हुई है और आम जनता के लिए कई सामाजिक सुरक्षाओं की घोषणा हुई है। श्री मोदी ने कहा कि अब मैं प्रधान संतरी हूं, देश की सम्पत्ति को लूटने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 365 दिनों में हमने बुरे दिनों, बुरी नीयत, बुरे कामों, बुरे कारनामों से मुक्ति दिलाने का काम किया है। उल्लेखनीय है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय का संबंध मथुरा से है। यहां के नगला चंद्रभान क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था।

मथुरा जन कल्याण रैली के अवसर पर 25 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से प्रश्नवाचक शैली में पूछा कि भाजपा सरकार बनने के बाद बुरे दिन गए या नहीं? उन्होंने कहा कि अब जिनके बुरे दिन आए हैं, वे चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। जिनके बुरे दिन अब आए हैं, उनके अच्छे दिन आने की अब कोई गारंटी नहीं है। अच्छे दिन आने के मोदी सरकार के दावे की कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचनाओं का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिनके बुरे दिन आए हैं, उन्हें चीखने चिल्लाने दीजिए। उन्हें तो चीखना ही है, उनकी परेशानियां मैं समझता हूं और हम ऐसा करेंगे कि बुरा करने वालों के और बुरे दिन आएंगे। बुरा करने वालों के सारे बुरे

कारनामे बंद होकर रहेंगे और देश को हम नई उंचाइयों पर ले जाएंगे।

श्री मोदी ने कहा कि ब्रज की भूमि के कण-कण में श्रीकृष्ण का वास है। सरकार चाहती तो एक वर्ष पूरा होने का जश्न किसी भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में कर सकती थी, लेकिन इसके लिए मथुरा को चुना गया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गांधी और लोहिया को अपना प्रेरणास्रोत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन तीन महापुरुषों ने देश की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने इन्हें भारतीय राजनीति का मार्गदर्शक बताया।

यूपीए सरकार पर सवाल उठाते हुए श्री मोदी ने अपने संबोधन में यूपीए को घोटालों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि अगर यह यूपीए सरकार एक वर्ष और रह गई होती और उसकी जगह नई सरकार नहीं चुनी होती, तो यह परिवर्तन नहीं आता। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष के शासनकाल में किसी तरह के घोटाले की खबर किसी ने नहीं सुनी होगी, जबकि यूपीए सरकार में यह बेहद आम बात थी। उन्होंने देश की राजनीति में बदलाव लाने के लिए लोगों का शुक्रिया भी अदा किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कांग्रेस को परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि देश की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाकर परिवारवाद की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि पिछले एक साल में कहीं से घोटाले की कोई खबर आई क्या? भाई भतीजावाद की खबर आई क्या? रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की खबर आई क्या? किसी नेता के दामाद या बेटे का कोई किस्सा कहानी हुई क्या? बुरे दिन गए कि नहीं? लूट का जमाना गया कि नहीं?

श्री मोदी ने कहा कि चुनाव के

बाद मैंने वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान संतरी बनूंगा और तिजोरी पर किसी पंजे को नहीं पड़ने दूंगा। मैंने यह वादा निभाया कि नहीं? लूट का खेल बंद कराया या नहीं?

श्री मोदी ने कहा कि इन दिनों कुछ लोग काफी परेशान हैं, उनकी परेशानी यह है कि सभी लोगों के अच्छे दिन आए लेकिन उनके लिए बुरे दिन आ गए। मैंने वर्षों से देश को लूट रहे लोगों के अच्छे दिन आने की गारंटी नहीं दी थी। हम देश को इस तरह से चलाएंगे कि उनके लिए और बुरे दिन आएंगे और उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। आपका पैसा अब कोई नहीं लूट सकेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग चीख चिल्ला रहे हैं, क्योंकि 60 सालों से दिल्ली के सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज गूंजती थी और दिल्ली में पॉवर सेंटर से ज्यादा पॉवर सर्किल का बोलबाला था। अभिमन्यु को आठ घेरे तोड़ने थे, लेकिन यहां तो सत्ता के ऐसे सैकड़ों घेरे थे।

आपके आशीर्वाद से सत्ता के ऐसे सैकड़ों घेरों को नष्ट कर दिया गया है। अब सत्ता के गलियारों में दलालों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए वे और चीख चिल्ला रहे हैं। उनके तो और बुरे दिन आयेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि मैं अब प्रधान संतरी हूं, देश की सम्पत्ति को लूटने नहीं दिया जायेगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 365 दिनों में हमने बुरे दिनों, बुरी नीयत, बुरे कामों, बुरे कारनामों से मुक्ति दिलाने का काम किया है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस वक्तव्य का श्री मोदी ने उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि एक रुपये में से 85 पैसे लूट लिए जाते थे। प्रधानमंत्री मंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि 100 से 100 पैसे लोगों तक जाएं और दलाल एक पैसा भी लूटने नहीं पाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बुरे दिन, कितने बुरे कर्म और कितनी अधिक बुराइयों का माहौल था और तब देश की जनता ने इस माहौल को बदलने और परिवर्तन लाने का फैसला किया। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर प्रहार जारी रखते हुए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कोयला की खदानें अपने चहेतों को कौड़ियों के दाम बेचीं, जबकि हमने एक साल के भीतर केवल 29 कोयला खदानें आवंटित करके तीन लाख करोड़ अर्जित किए। लूटने वालों के दिन खत्म हुए या नहीं, अपने चहेतों को खदान देने के दिन खत्म हुए या नहीं?

अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बदलने के जनता के फैसले के कारण उनकी सरकार सुशासन देने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है और जो यह चमत्कार, परिवर्तन और विश्वास दिख रहा है, वह जनता के इसी फैसले के कारण है।

किसानों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 60 वर्षों में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। 3 लाख मरे या एक किसान मरे, सरकार किसी की भी हो, हमें राजनीति नहीं करनी है। आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना है। हमें मिलकर समस्या का हल निकालना है।

प्रधानमंत्री ने इस संबंध में किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बूंद बूंद पानी का उपयोग, सिचाई योजनाओं आदि का जिक्र किया। यूरिया की कालाबाजारी और उद्योगों में इसके चोरी से उपयोग पर लगाम लगाने का दावा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यूरिया पर नीम की परत चढ़ाने से अब इसका खेती के अलावा अन्य काम में उपयोग नहीं होगा और इसकी चोरी रुकेगी।

उन्होंने कहा कि जनधन योजना से मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत गरीबों को मिलने वाला धन अब बिचौलिए लूट नहीं पाएंगे और यह सीधे उनके खाते में जाएगा।

उन्होंने कहा कि रसोई गैस की सब्सिडी की चोरी रोकने के लिए सरकार ने इसे सीधे बैंक खातों में डालना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं होने के कारण पहले रसोई गैस के सिलिंडरों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी होती थी।

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार नदियों को जोड़ने, पानी को व्यर्थ बह जाने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और दावा किया कि उनकी सरकार पांच साल के भीतर देश के हर किसान को 24 घंटे बिजली मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने छोटे-छोटे कारोबारियों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा बैंक बनाया है। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपति नहीं, छोटे कारोबारी ही हैं, जो सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराते हैं।

जन कल्याण रैली से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल स्मृति भवन गए और वहां अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया गया है। भाजपा ने इसे 'जनकल्याण पर्व' नाम दिया है। ■

अन्नदाता सुखी भव : हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

भाजपानीत एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर प्रधानमन्त्री द्वारा जनता को लिखे गए पत्र का मूल पाठ

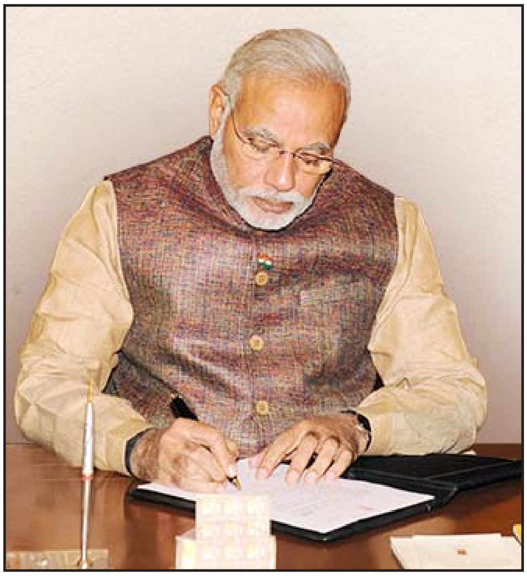

मेरे प्यारे देशवासियों,

पिछले वर्ष आज के दिन जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री का दायित्व मिला। मैं स्वयं को 'प्रधान सेवक' मानकर अपनी जिम्मेदारी इसी भावना से निभा रहा हूं। अन्त्योदय हमारे राजनैतिक दर्शन का मूल मंत्र है। प्रमुख फैसले लेते समय हमेशा वंचित, गरीब, मजदूर और किसान हमारी आंखों के सामने रहते हैं। जन-धन योजना में हर परिवार का बैंक खाता और प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेन्शन योजना इसी का प्रमाण हैं।

'अन्नदाता सुखी भव:' हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे किसान अथक मेहनत कर देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, बिजली की बेहतर उपलब्धता, नई यूरिया नीति, कृषि विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के साथ हम मजबूती से खड़े रहे। सहायता राशि को डेढ़ गुना किया तथा पात्रता मापदंड को अधिक किसान-हितैषी बनाया।

भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी, नीति-आधारित प्रशासन एवं शीघ्र निर्णय हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं। पहले प्राकृतिक सम्पदा जैसे कोयला या स्पैक्ट्रम का आबंटन मनमानी से, चहेते उद्योगपतियों को होता था। किन्तु देश के संसाधन देश की सम्पत्ति हैं। सरकार का मुखिया होने के नाते मैं उसका ट्रस्टी हूं। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि इनका आबंटन नीलामी से होगा। कोयले के अब तक हुए आबंटन से लगभग तीन लाख करोड़ रुपए और स्पैक्ट्रम से लगभग एक लाख करोड़ रुपये की आमदनी होगी!

सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए भरोसेमंद सरकार आवश्यक होती है। जब हमारी सरकार बनी उस समय आर्थिक स्थिति डावांडोल थी। महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों से विगत वर्ष में भारत विश्व की तीव्रतम विकास वाली अर्थव्यवस्था बनी, महंगाई नियंत्रित हुई और पूरे वातावरण में नए उत्साह का संचार हुआ। विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पूंजी निवेश बढ़ा है। 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' अभियान का उद्देश्य हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान कराना है। हमने मुद्रा बैंक की स्थापना की जिससे छोटे-छोटे रोजगार चलाने वाले भाई-बहनों को दस हजार रुपए से दस लाख रुपए तक के बैंक-ऋण सुलभ होंगे। हमने कालाधन वापस लाने का वादा किया था। सरकार बनते ही पहला निर्णय कालेधन पर एसआईटी गठन करने का था। फिर हमने विदेशों में कालाधन रखने वालों को कड़ी सजा देने के लिए कानून बनाया।

'स्वच्छ भारत अभियान' की सोच है कि बहू-बेटी को खुले में शौच न जाना पड़े, शौचालय के अभाव में बेटियां स्कूल न छोड़े और गंदगी से मासूम बच्चे बार-बार बीमार न पड़ें। बालकों की तुलना में बालिकाओं की गिरती संख्या बहुत चिंता

शेष पृष्ठ 22 पर

राजग सरकार का एक वर्ष

संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने उठाये मजबूत कदम : अमित शाह

गत 26 मई, 2015 को भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसका एक साल पूरा हुआ। देश के लोकतंत्र के इतिहास के लिए और भाजपा के लिए भी गत साल कई मायनों में नए रिकार्ड स्थापित करने वाला रहा। तीस साल के बाद इस महान देश में किसी पार्टी को बहुमत देने का फैसला 2014 के चुनाव में इस देश की जनता ने किया। एक निर्णायक जनादेश किसी एक पार्टी को 30 वर्षो बाद मिला। इस देश की जनता ने आजादी के बाद पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका दिया। ये दोनों चीजें देश के लोकतंत्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

भाजपा के लिए यह गौरव की बात है कि देश की जनता ने जो पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल को सरकार बनाने का मौका दिया वो भाजपा को दिया। देश के सभी हिस्सों से करीब-करीब भाजपा और एनडीए का प्रतिनिधित्व आज संसद में, इस सरकार में साझीदार है। अरूणाचल में भाजपा का सांसद है तो कच्छ में भी भाजपा का सांसद है। लेह-लद्दाख में भाजपा का सांसद है तो कन्याकुमारी में भी भाजपा का सांसद है। पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण चारों ओर भाजपा को इस देश की प्रजा ने सम्मानित किया है और हमें सरकार बनाने का मौका दिया है। आज यह सरकार एक वर्ष समाप्त कर रही है।

देश के सभी हिस्सों से करीब-करीब भाजपा और एनडीए का प्रतिनिधित्व आज संसद में, इस सरकार में साझीदार है। अरूणाचल में भाजपा का सांसद है तो कच्छ में भी भाजपा का सांसद है। लेह-लद्दाख में भाजपा का सांसद है तो कन्याकुमारी में भी भाजपा का सांसद है। पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण चारों ओर भाजपा को इस देश की प्रजा ने सम्मानित किया है और हमें सरकार बनाने का मौका दिया है।

इस देश में सरकार के प्रति अविश्वास का जो संकट पैदा हुआ था उसको इस सरकार ने समाप्त किया है। पहले देश की सरकार पर इस देश की जनता को भरोसा नहीं था कि यह सरकार देश को कहां पर ले जाएगी। देश के प्रधानमंत्री को देश की कैबिनेट पर भरोसा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं था। आज वो विश्वास का संकट टल गया है। दुनिया भी बड़े भरोसे से आनंद और आश्चर्य से भारत की प्रगति देख रही है। हर क्षेत्र में इस सरकार ने नई-नई पहल की है और परिणाम भी पाए हैं।

यह सरकार विज़िबल सरकार रही है। पहले सरकार को ढूंढ़ना पड़ता था। अब शायद मीडिया से भी आगे आकर सरकार प्रोएक्टिव होकर जनता की दिक्कत के समय में जनता के साथ दिखाई पड़ रही है। जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आती है तो कुछ ही घंटों में वहां मंत्री और प्रधानमंत्री दिखाई पड़ते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में अगर भूकंप आता है तो तुरंत ही सरकार प्रोएक्टिव होकर नेपाल में दिखाई देती है। तमिलनाडु में यदि भारतीय मछुआरों पर संकट आता है, फांसी दी जाती है तो भारत सरकार हस्तक्षेप करती है। किसी क्रिश्चियन पादरी को अफगानिस्तान में अगवा किया जाता है तो भारत सरकार दखल करके उसको छुड़ाकर लाती है।

इस सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को पुनः स्थापित किया है। एक जमाना था जब हर मंत्री दस साल तक अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। भाजपा इस स्थिति में परिवर्तन लाई है। आज हरेक मंत्री स्वतंत्रतापूर्वक अपने मंत्रालय का काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। उन पर कोई मंत्री समूह नहीं थौपे गए हैं। मंत्रियों को काम करने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय का गौरव पुनः स्थापित हुआ है। यह सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर आई है। जैसे ही समस्या सामने आती है इसके निवारण के लिए यह सरकार तुरंत प्रोएक्टिव होकर अगर जरूरी है तो नीतियों में परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहती है और इसके अच्छे परिणाम हमें

मिले हैं।

10 वर्षों तक देश की जनता किसी एक चीज से अगर सबसे ज्यादा त्रस्त थी तो वह भ्रष्टाचार था। 10 वर्षों तक हर महीने कोई न कोई घपला या घोटाला, लाखों करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार जनता के सामने आता था, जो जनता के आत्मविश्वास को हिलाकर रख देता था। दुनिया में भी हिन्दुस्तान की साख इन घोटालों के कारण दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही थी। लोकसभा चुनाव के वक्त हमने वचन दिया था कि हम भ्रष्टाचार को इस व्यवस्था से उखाड़कर फेंक देंगे। मुझे बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि एक वर्ष में हमारे विरोधी भी इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। ये भाजपा की मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

लोकसभा चुनाव के वक्त हमने वचन दिया था कि हम भ्रष्टाचार को इस व्यवस्था से उखाड़कर फेंक देंगे। मुझे बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि एक वर्ष में हमारे विरोधी भी इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। ये भाजपा की मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

यूपीए के कुछ मंत्रियों द्वारा जीरो लॉस की थ्योरी बार-बार प्रतिस्थापित की जाती रही कि कोयला में कोई नुकसान नहीं हुआ, स्पेक्ट्रम में कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भाजपा की मोदी सरकार ने 220 खदानें जो कांग्रेस ने आबंटित की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया उसमें से 29 खादानों की पारदर्शी नीलामी करके दो लाख करोड़ से ज्यादा भारत के खजाने में इज़ाफा किया है। इससे स्पष्ट होता है कि कैग ने नुकसान को कुछ कम ही आंका था। एक-तिहाई क्षमता वाले स्पैक्ट्रम की नीलामी भाजपा की मोदी सरकार ने की और एक लाख नौ हजार करोड़ रुपया देश की तिजोरी में जमा हुआ। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कैग ने नुकसान को कुछ कम ही आंका था। आज एक वर्ष के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि कांग्रेस के नेता फिर से एक बार जरा जीरो लॉस वाली थ्योरी को देश के सामने रखने का साहस करें।

काले धन पर बार-बार भाजपा पर कांग्रेस के नेता निशाना लगाते हैं कि कालेधन में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि 68 वर्ष की आजादी में 60 वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने कालेधन की रोकथाम के क्या काम किया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद डेढ़ साल तक कांग्रेस की सरकार ने एसआईटी बनाने का काम नहीं किया था। भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट का पहला ही फैसला कालेधन की जांच के लिए एसआईटी बनाने का हुआ। यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है कि हम कालेधन की रोकथाम के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। तीन साल से दुनिया भर के देशों से जो सूचनाएं आकर पड़ी थी उन सूचनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। हमारी सरकार बनने के बाद 45 दिनों में करीब-करीब 700 सूचनाओं को हमने एसआईटी को जांच के लिए दे दिया और आज एसआईटी उस पर जांच कर रही है। भाजपा की सरकार कटिबद्धता से कालेधन पर जो वैश्विक समाधान हुए इस पर कानूनी रूप से कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है। इसीलिए देश की संसद में वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहली बार सजा का प्रावधान वाला कानून लेकर मोदी सरकार आई है। आजादी के बाद पहली बार एक कानून ऐसा बना है जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यह कानून बनने के बाद यह बात गारंटी से कही जा सकती है कि इस देश में से फूटी कोड़ी भी कालेधन के रूप में बाहर जाने का रास्ता भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया है।

संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने जितना किया उतना शायद आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। योजना आयोग भंग कर नीति आयोग में राज्यों के सीएम को शामिल किया गया जिससे योजनाएं राज्यों की आवश्यकता के अनुरूप बने। इससे विकास और कल्याणकारी जो भी योजनाएं बनेंगी उसे वास्तविक स्वरूप देने से जनता को फायदा होगा। खदानों की पारदर्शी निलामी से आने वाली पूरी रकम राज्यों के विकास के लिए देने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। संघीय ढांचे के अनुरूप राज्यों को साथ लेकर चलने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय करों के लाभांश में 10 फीसदी वृद्धि करते हुए राज्यों का हिस्सा 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया। कोयला खदान की नीलामी से जितनी

भी राशि आएगी वह बिना किसी पक्षपात के शत-प्रतिशत राज्यों को जाएगी। यह संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार टीम इंडिया की भावना को मोदी सरकार ने देश के समक्ष रखा है।

जब अटल जी को विरासत में 4.4 प्रतिशत विकास दर वाली अर्थव्यवस्था मिली थी तो 6 साल बाद विकास दर को 8.4 प्रतिशत तक पहुंचा कर यूपीए के हाथ में सत्ता सौंपा था। 10 साल बाद 4.4 प्रतिशत विकास दर वाली अर्थव्यवस्था मोदी जी को मिला। 1 साल में हमने जीडीपी को 5.7 फीसदी तक पहुंचाने में सफलता पाई। यह आंकड़े साबित करती है कि कांग्रेस की सरकार जब आती है तो विकास दर गिरती है और भाजपा की सरकार जब आती है तो विकास दर बढ़ती है। बजट घाटा नियंत्रण, व्यापार घाटा नियंत्रण, एफडीआई में वृद्धि-सभी पैमानों पर भाजपा की सरकार अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

लोकसभा चुनाव के समय हमने कहा था कि हमारी प्राथमिकता गरीबों को विकास की अग्रिम पंक्ति में लाना है। हमने जनधन योजना के तहत 15 करोड़ गरीब परिवारों का अकाउंट खुलवाकर उन्हें अर्थतंत्र से जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस बजट के अंदर मोदी सरकार दो नई योजनाएं लेकर आई है, पहला साल के 12 रुपए प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा और दूसरा 330 रुपए पर 2 लाख का जीवन बीमा योजना।

यदि बेरोजगारी का समाधान कर लेते हैं तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। बेरोजगारी दूर करने के लिए मोदी सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल डेवलपमेंट' जैसी पहल बेरोजगारी दूर करने में बेहद कारगर साबित होंगी। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को विश्व के अन्य देशों से अच्छा रिस्पांस मिला है। कृषि पर निर्भरता कम करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमने मुद्रा बैंक की योजना शुरू की। मुद्रा बैंक के जरिए 10 हजार से 10 लाख रूपये का लोन उपलब्ध कराने की योजना है।

बुनियादी ढांचे के अंतर्गत यूपीए के समय सड़क 5.3 प्रतिशत की रफ्तार से बन रही थी, अब 10.1 प्रतिशत बन रही है। यूपीए के समय बिजली उत्पादन 6 फीसदी थी अब बढ़कर 8.5 फीसदी हो गई है यानी 2.5 फीसदी की वृद्धि। दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत 44,000 करोड़ दिए गए ताकि राज्यों को 24 घंटे बिजली मिले।

'पहल योजना' के तहत लोगों को उनकी एलपीजी सब्सिडी की रकम सीधे उनके खाते में पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है और प्रधानमंत्री के आग्रह पर 2.5 लाख लोगों ने सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिया है।

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 14 प्रतिशत असिंचित भूमि को सींचन के दायरे में लाया जाएगा। पहले कुदरती आपदा आती थी तो किसानों को सही मुआवजा नहीं मिलता था। हमने पहले के 50 फीसदी नुकसान के साथ-साथ 33 फीसदी नुकसान पर भी मुआवजा देना तय किया है। मुआवजे का दायरा एक हेक्टेयर से बढ़ाकर दो हेक्टेयर कर दिया गया है। मिट्टी हेल्थ कार्ड के तहत कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है, खेत में कितना पानी कितने अंतराल पर डालनी है, कौन सी फसल को अधिकतम फायदा देगा इसकी सलाह दी जाती है। राजस्थान में इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई है। यूपीए के समय डब्ल्यूटीओ में एक समझौता हुआ था कि किसानों को एमएसपी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमने दृढ़तापूर्वक अपनी बात रखते हुए कहा कि किसानों के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। डब्ल्यूटीओ में हमारी जीत हुई। राजनीतिक इच्छाशक्ति का यह बेहतरीन उदाहरण है।

सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि, संवाद और संस्कृति के आधार पर विदेश नीति तय करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों की यात्राएं कीं। केंद्र की मोदी सरकार ने एक ठोस रक्षा नीति बनाई है। हमने तीनों सेनाओं के साधनों के लिए 10 साल का एक रोडमैप तैयार कर उन्हें आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत होकर सीमा की सुरक्षा करें।

सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि, संवाद और संस्कृति के आधार पर विदेश नीति तय करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों की यात्राएं कीं। केंद्र की मोदी सरकार ने एक ठोस रक्षा नीति बनाई है। हमने तीनों सेनाओं के साधनों के लिए 10 साल का एक रोडमैप तैयार कर उन्हें आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत होकर सीमा की सुरक्षा करें। ■

करनाल (हरियाणा)

हमने पारदर्शी सरकार दी : अमित शाह

केंद्र में मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में समारोह का आयोजन किया। इसी के अंतर्गत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में पार्टी की 200 बड़ी रैलियों की योजना की शुरुआत की।

गत 25 मई 2015 की रैली में श्री शाह ने मोदी सरकार एक साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों की स्मारिका का विमोचन किया। यह स्मारिका 13 भाषाओं और 5 बोलियों में प्रकाशित की गई है।

मोदी सरकार की उपलब्धियाँ को गिनाने के साथ ही श्री शाह ने कांग्रेस से 60 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि हमने एक साल में नींव तैयार की है और अगले चार साल में भव्य इमारत बनाएंगे।

मुख्य बातें

- एक साल की सरकार के बाद हमने एक साल में ही हिसाब दे दिया। स्वस्थ परंपरा शुरू की। कांग्रेस भी अपने साठ सालों का हिसाब दे।
- काले धन को वापस लाने के लिए मोदी सरकार गंभीर है। एक भी फूटी कौड़ी देश से बाहर नहीं जाएगी।
- रक्षा के मोर्चे पर हमने सराहनीय काम किए। सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के सैनिक का सिर काटने की हिम्मत अब किसी में नहीं है।
- बेहरतीन कामों की शुरुआत कर मोदी ने जो नींव डाली, उस पर चार साल में भव्य इमारत बनाएंगे।
- मेक इन इंडिया व कौशल विकास के जरिए रोजगार देंगे।
- पांच साल में 14 प्रतिशत सिंचाई भूमि का लक्ष्य रखा।
- किसानों के हित के लिए कई अहम फैसले लिए।
- यूपीए सरकार में 12 लाख करोड़ के घपले हुए। मोदी सरकार में विपक्ष कोई कमी नहीं निकाल पा रहा।
- हमने एक साल में पारदर्शी सरकार दी और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगने दिया।

पणजी (गोवा)

यूपीए सरकार के दौरान विश्वास का संकट

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में लोगों का भरोसा बहाल किया है तथा देश को विश्वास के संकट से राहत दिलायी है जो यूपीए शासनकाल के दौरान संविधानेतर शक्तियों के कारण व्याप्त था।

श्री शाह ने 28 मई 2015 को गोवा के एक दिवसीय

दौरे में संवाददाताओं से कहा कि संप्रग सरकार के दौरान देश में विश्वास का संकट व्याप्त था। अब भाजपा नीत सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में भरोसा बहाल किया है। उन्होंने दावा किया कि संप्रग शासनकाल में कैबिनेट, नौकरशाही एवं लोगों का प्रधानमंत्री में भरोसा उठ गया था। अब सभी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भरोसा है। भाजपा नीत सरकार ने देश को

इस विश्वास के संकट से राहत दिलवायी है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि संप्रग अपने दस साल के शासनकाल में 12 लाख करोड़ रुपये के घोटालों में शामिल रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में शासन के पहले वर्ष में विपक्ष भ्रष्टाचार के एक भी मुद्दे की ओर इशारा नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा, हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का आश्वासन दिया था जो हमने प्रदान की है।

हमने उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगा दी है। श्री शाह ने कहा, भाजपा ने आश्वासन दिया था कि जब हम सत्ता में आयेंगे तो हम विदेश में रखे काले धन को बेनकाब करेंगे। संप्रग सरकार ने काले धन के मुद्दे पर कभी नहीं बोला लेकिन मोदी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में एसआईटी का गठन कर दिया और जांच शुरु हो गयी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ले आयी है।

सूरत (गुजरात)

मोदी सरकार ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया

केंद्र सरकार का एक साल पूरा होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 27 मई को सूरत दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनाई। श्री शाह ने कहा कि एक साल पहले यूपीए के शासनकाल के दौरान देश में हताशा और

निराशा का माहौल था, आर्थिक विकास दर काफी नीचे थी और युवा निराश एवं महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहीं थीं।

देश के बाहर यह धारणा बलवती थी कि भारत की विकास गाथा समाप्त हो गई है। आज एक साल बाद हम कह सकते हैं कि देश की परिस्थिति बदली है। सरकार सभी जगह दिखती है। एक साल की बड़ी उपलब्धि यह है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी गई है, विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। यह कैग की रिपोर्ट थी। काला धन मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कानून बनाकर काला धन विदेश भेजने वालों को 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया है। अब कोई काला धन बाहर भेजने का हिम्मत नहीं करेगा। विदेश से काला धन लाने के तहत एसआईटी का गठन कर सभी जानकारी सौंपी जा चुकी है।

श्री शाह ने कहा कि सरकार ने केंद्र और राज्य के संबंध बेहतर बनाकर संघीय ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया है। योजना आयोग को बंद कर नीति आयोग बनाया गया है। योजनाएं जितनी वास्तविक होंगी, उन्हें लागू करने में उतनी ही सरलता होगी। श्री शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार कोल ब्लॉक से होने वाली आवक राज्यों के विकास पर खर्च करेगी। बजट में राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया गया है।

श्री शाह ने प्रधामंत्री जन-धन योजना को देश की गरीबी दूर करने का व्यावहारिक प्रयास बताया। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी हटाने की बात करने वाली पिछले सरकारें इस तरह का काम नहीं कर सकीं। देश के 60 करोड़ लोगों के पास बैंक एकाउंट नहीं थे। सरकार ने एक साल के अंदर ही 15 करोड़ परिवारों के एकाउंट खुलवाए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गए हैं। इसके अलावा उन्हें दुर्घटना एवं जीवन बीमा से महज 342 रुपए में जोड़ा गया है।

मुद्रा बैंक की योजना बेरोजगारी दूर करने में कारगर साबित होगी। वर्ष 2019 तक हरेक गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का संकल्प है।

प्राकृतिक आपदा में किसानों को पहले 50 फीसदी नुकसान होने पर राहत दी जाती थी, अब 33 फीसदी नुकसान पर भी राहत दी जाएगी। इसके अलावा एक हेक्टेयर के बजाय दो हेक्टयर तक के नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। ■

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ पार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शुरु की गई तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण कराने वालों की संख्या 10

करोड़ पार कर जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत एक महीने में पंजीकरण 10 करोड़ को पार कर गए हैं। यह अत्यंत खुशी की बात है। इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि हमारे दस करोड़ भाई बहन सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के अंतर्गत शामिल हो गए हैं।

'सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति लोगों का उत्साह और बैंकों के प्रयास भी सराहनीय रहे हैं। इन्हीं की बदौलत रिकॉर्ड पंजीकरण संभव हो पाया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सुरक्षा की तीन योजनाओं– अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को मई में लॉन्च किया था।

अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल पूरा होने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी जो उनके योगदान पर निर्भर करेगी।

योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित व्यक्ति किस उम्र में योजना से जुड़ता है। इस योजना के लिये न्यूनतम उम्र 18 साल तथा अधिकतम उम्र 40 साल है।

इसमें अंशधारक के लिये योगदान की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है। सरकार की ओर से निश्चित पेंशन लाभ

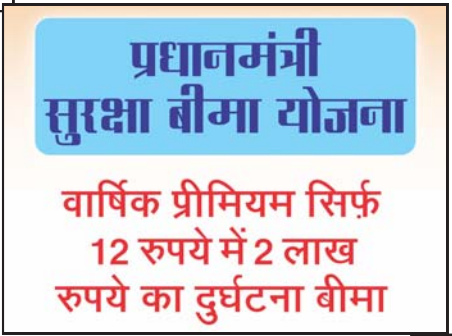

की गारंटी होगी। सरकार इस पेंशन योजना में भागीदारी करने वाले अंश धारकों की तरफ से वार्षिक प्रीमियम का 50 प्रतिशत या फिर 1,000 रुपये का योगदान करेगी। इनमें जो भी कम होगा वह राशि सरकार देगी। सरकार की तरफ से यह योगदान पांच साल तक किया जाएगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा धारक को 12 रुपये की सालाना बीमा पर दो लाख रुपये की निजी दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना बैंक के बचत खाता धारक के लिए 18 से 70 वर्ष की अवस्था के लिए लागू है। इसके तहत बीमा लेने वाले बैंक को हर साल 31 मई या उससे पहले खुद खाते से प्रीमियम काट लेने की अनुमति देंगे, जिस पर बीमा धारक को एक जून से अगले साल 31 मई तक दुर्घटना बीमा सुरक्षा हासिल होगी।

इस बीमा का खुद-ब-खुद नवीनीकरण होता रहेगा। बीमा कवर 1 जून से लागू होगा।

प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एक प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी हैं जिसके अंतर्गत किसी भी कारण से धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि मिलने का प्रावधान हैं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत धारक के परिवार जनों को 2 लाख रुपये की राशि मिलेगी।

योजना को प्रति वर्ष 31 मई से

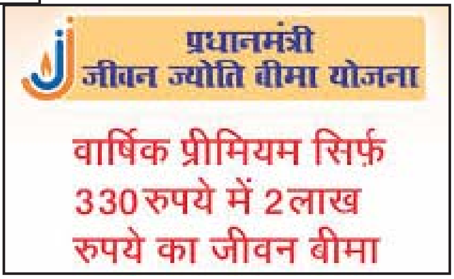

पहले रिन्यू करवाना होगा जिसके लिए प्रीमियम शुल्क 330 रुपये प्रति वर्ष तय किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाला व्यक्ति ही शामिल हो सकता हैं। ■

भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यसमिति बैठक

"मोदी सरकार ने देश का सम्मान बढ़ाया"

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एक साल पहले देश की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसके तहत 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद इस सरकार ने जिस प्रकार काम किया है उसके संबंध में हमारे विरोधी भ्रांति फैलाने में लगे हैं, लेकिन उससे घबड़ाना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि सत्ता में आने के बाद देश में से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे। दस साल तक यूपीए का शासन चला, एक के बाद एक घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ के घोटाले यूपीए कार्यकाल में हुए और 15 साल तक महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का शासन रहा और यहां भी न जाने कितने घोटाले हुए। एक साल तक हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। एक साल बाद जब 26 मई से 31 मई के बीच जब हम जनता के पास जाएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का हिसाब-किताब लेकर जाएंगे।

हमने कहा था कि सरकार के कामकाज में परिवर्तन लाएंगे। यूपीए सरकार 10 साल तक चली लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि सरकार कहां से चलती है। हर मंत्री अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री था और प्रधानमंत्री को पता ही नहीं था कि वे प्रधानमंत्री हैं। 10 साल बाद हमने प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा स्थापित की और सारे मंत्रि-समूह को भंग कर सारे मंत्रियों के हाथ में संबंधित मंत्रालय का अधिकार दिया गया और वे स्वतंत्र तरीके से काम कर सकें, ऐसा माहौल तैयार किया गया।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के समय एसआईटी गठन का निर्देश दिया था लेकिन डेढ़ साल तक नहीं हुआ। एनडीए ने पहली कैबिनेट में पहला निर्णय एसआईटी गठन का लिया। हमने डेढ़ माह में सूची एकत्रित कर एसआईटी को दी। हमने इसके लिए कानून भी बनाकर सजा निर्धारित कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 68 में 60 साल शासन किया लेकिन न तो काले धन वापस लाने का काम किया और न बाहर जाने से रोकने का ही काम किया। उन्होंने कहा कि जिसने 60 साल तक कुछ नहीं किया उन्हें एक साल का हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से अपील करते हुए कहा कि वे पहले 60 साल का हिसाब देश की जनता को दें कि उन्होंने काले धन पर क्या किया?

संघीय ढांचे पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि संघीय ढांचे के लिए बहुत बातें होती थीं मगर 60 सालों तक भाषण के अलावा इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार भाजपा सरकार ने संघीय ढांचा मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाया। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर हमने राज्यों का लाभांश 10 फीसदी बढ़ाते हुए उसे 32 फीसदी से 42 फीसदी कर दिया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग में योजनाओं के बनने के स्तर से ही राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई, इससे विकास और कल्याणकारी जो भी योजनाएं बनेंगी उसे वास्तविक स्वरुप देने में बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि खदानों की पारदर्शी निलामी से आने वाली पूरी रकम राज्यों के विकास के लिए देने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि संघ को मजबूत करने के लिए संघ के अंग राज्य को मजबूत करना होगा।

श्री शाह ने कहा कि पहले कुदरती आपदा आती थी तो किसानों को सही मुआवजा नहीं मिलता था। हमने पहले के 50 फीसदी नुकसान के साथ-साथ 33 फीसदी नुकसान पर भी मुआवजा देना तय किया है। हमने सहायता राशि भी बढ़ाई है। पहले यदि 100 रुपया सहायता राशि मिलती थी उसे अब 150 रुपया कर दिया गया है।

लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, महंगाई का मुद्दा छाया रहा। उस समय थोक मूल्य सूचकांक 6 से 7 प्रतिशत थी जो अब घटकर -2.33 प्रतिशत पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई की दर 1 साल पहले 8.25 प्रतिशत थी अब 5.6 प्रतिशत पर सीमित हो गई है।

एक साल पूर्व की तुलना वर्तमान से करते हुए श्री शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, महंगाई का मुद्दा छाया रहा। उस समय थोक मूल्य सूचकांक 6 से 7 प्रतिशत थी जो अब घटकर -2.33 प्रतिशत पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई की दर 1 साल पहले 8.25 प्रतिशत थी अब 5.6 प्रतिशत पर सीमित हो गई है। श्री शाह ने कहा कि इस सरकार ने अर्थतंत्र को पटरी पर लाने का सफल प्रयास किया है। जब अटल जी को विरासत में 4.4 प्रतिशत विकास दर वाली अर्थव्यवस्था मिली थी तो 6 साल बाद विकास दर को 8.4 प्रतिशत तक पहुंचा कर यूपीए के हाथ में सत्ता सौंपा था। 10 साल बाद 4.4 प्रतिशत विकास दर वाली अर्थव्यवस्था मोदी जी को मिला। 1 साल में हमने जीडीपी को 7.5 फीसदी तक पहुंचाने में सफलता पाई। उन्होंने कहा कि बजट घाटा नियंत्रण, व्यापार घाटा नियंत्रण, एफडीआई में वृद्धि-हर मोर्चे पर भाजपा की सरकार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अर्थतंत्र को पटरी पर लाने का भगीरथ प्रयास भाजपा की सरकार ने एक साल में किया है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अगर कोई बड़ा काम किया है तो देश का सम्मान बढाने का काम किया है। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं पर भी जाते थे तो किसी को मालूम ही नही पड़ता था। जहां-जहां प्रधानमंत्री जी गये, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, चाहे श्रीलंका हो, हजारों-हजारों का हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ता है। विदेशी सरकारें भी भारत को प्रमुख मित्र बनाने की दौड़ में लगी हुई है।

जो सम्मान मोदी जी को मिल रहा है वह सम्मान नरेन्द्र मोदी जी का नहीं है और न ही वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी का है बल्कि वह सम्मान सवा सौ करोड़ देशवासियों का है। आज हम विश्व को संदेश देकर आते हैं। दुनिया यह मानती है कि भारत आने वाले समय का बड़ा प्लेयर है दुनिया इसी आशा के साथ हमको देख रही है कि उन्हें यहां बाजार भी दिखता है, सम्भावनाएं भी दिखती हैं और सशक्त देश भी दिखता है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान, नमामि गंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी कई योजनाओं को हमने जनांदोलन में तब्दील किया है।

श्री शाह ने कहा कि देश एक साल में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस आशा से इस देश की जनता ने हमें जनादेश दिया था उससे ज्यादा काम करके 5 साल बाद फिर से जनता के बीच जाएंगे। जो एक साल बीता है, वह जन अपेक्षाओं की संतुष्टि का है। हम संपर्क अभियान लेकर निकले हैं, भाजपा के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में फैल जाएं।

उन्होंने कहा कि एक हाथ में सरकार की एक साल की उपलब्धियां और दूसरे हाथ में ध्वज लिए घर-घर जाएं, जागृति लाएं और उन्हें बताएं कि आपकी सरकार देश को गौरव दिलाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अच्छे ढंग से काम किया है। यहां भी 15 साल से भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ था जिसे खत्म करने में हम सफल रहे हैं। यहां सरकार बनने के बाद पहली बार प्रदेश कार्यकारिणी हो रही है और इतने सारे कार्यकर्ता प्रदेश भर से आए हैं। 26 मई से 1 जून तक इस सरकार का एक सप्ताह हम मनाने वाले हैं, जनकल्याण सभा मनाने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता इसमें जुट जाएं और बिना किसी माध्यम के सीधे जनता तक पहुंच बनाने की आदत डालें। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी को आपसे अपेक्षा है कि आप सब परिश्रम करेंगे, भाजपा को विजय दिलाएंगे। ■

भारत-बांग्लादेश न केवल पास-पास बल्कि साथ-साथ : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के पहले वर्ष में 18 देशों की सफल यात्राएं की। इससे पूरे विश्व में भारत के प्रति न केवल नजरिया बदला है, बल्कि विकसित राष्ट्र भी भारत को एक उभरती शक्ति के रूप में देख रहे हैं। श्री मोदी की इन विदेश यात्राओं से देश में निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ ही अन्य देशों के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ेगा। इससे देश की प्रगति के साथ-साथ नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न होंगे। विदेश यात्राओं की इस सफल कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे वर्ष की शुरुआत में ही बांग्लादेश की दो दिवसीय ऐतिहासिक सफल यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सीमा समझौता सबसे अहम है।

ऐतिहासिक सीमा समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6-7 जून को बांग्लादेश की दो दिवसीय सफल ऐतिहासिक यात्रा की। यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। चाहे सीमा समझौता हो या सामरिक क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने का प्रयास या फिर जल व सड़क मार्ग से दोनों देशों को जोड़ने की पहल। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को करीब लाने की कोशिश की है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो देशों ने सीमा समझौते को आपसी बातचीत और सहमति के जरिए सुलझाया हो। भारत और बांग्लादेश ने 41 साल से लंबित मसले को सुलझाकर नया इतिहास रचा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना की मौजूदगी में भूमि समझौते के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया। भू-सीमा समझौते के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी

भी मौजूद थीं। श्री मोदी ने ट्वीट किया कि भूमि अदला-बदली से संबंधित दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया। इस तरह दोनों देशों ने इतिहास रचा।

16 मई 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख मुजीबुर्रहमान के बीच हुए समझौते में विवादित 161 गांवों के भाग्य का फैसला किया गया था। बांग्लादेश की संसद ने इस समझौते का अनुमोदन तत्काल कर दिया था। लेकिन भारत में इसको संसद से मंजूरी मिलने में 41 साल लगे। पिछले माह ही भारतीय संसद में इस समझौते को मंजूरी मिली। समझौते के प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर दोनों पक्षों ने 6 सितंबर 2011 को किए थे।

समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश को 17160 एकड़ जमीन दी है और बांग्लादेश ने भारत को 7110 एकड़ जमीन दी है। इससे दोनों देशों की सीमाएं बदल गई हैं। भूमि सीमा समझौते के अमल में आने से अवैध रूप से बांग्लादेशियों के भारत में घुसने और बसने का मसला हल हो सकेगा। इस समझौते को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रेखांकित करते हुए कहा कि अगर कोई सोचता है कि जमीन इधर गई या उधर गई तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ये दिल को जोड़ने वाला समझौता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच आंतरिक जल-पारागमन को लेकर भी समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच बंगाल की खाड़ी का एक बड़ा क्षेत्र जल सीमा से जुड़ा हुआ है। लेकिन आवागमन के लिए इसका उपयोग न के बराबर होता रहा है। लेकिन आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देश की सरकारों ने जल पारागमन समझौता किया है, जो आने वाले समय में ढाका और कोलकाता के बीच सेतु का काम करेगा।

दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए कोलकाता-ढाका-अगरतला और ढाका-शिलांग-गुवाहाटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस बस सेवा से कोलकाता से अगरतला के बीच 1650 किलोमीटर की दूरी घटकर 500 किलोमीटर रह जाएगी। क्योंकि पहले वाया गुवाहाटी जाना पड़ता था। लिहाजा, नई बस लिंक के चलते ज्यादा फायदा भारतीयों को है। वहीं, ढाका-शिलांग-गुवाहाटी के बीच बस सेवा शुरू होने से दोनों देशों के लोगों को फायदा मिलेगा।

सामरिक क्षेत्र में समझौता

भारत और बांग्लादेश के बीच एक और बेहद महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है वह है, चटगांव बंदरगाह तक भारत की पहुंच। भारत अब व्यापारिक और युद्धपोत यहां खड़ा कर सकता है। यह चीन को सामरिक दृष्टि से घेरने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मालूम हो कि चीन भारत को समुद्री सीमा पर घेरने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच इस समझौते से बांग्लादेश के जरिए चीन के वर्चस्व को कम करने में भारत को मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश के बीच 22 अन्य आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत ने बांग्लादेश को दो अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की। इससे भारत के मेक इन इंडिया के प्रयास को बल मिलेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश में बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए दो पावर प्लांट लगाने पर समझौता हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मुक्ति संग्राम पुरस्कार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से बांग्लादेश मुक्ति

संग्राम पुरस्कार हासिल किया। यह पुरस्कार ढाका में एक समारोह में बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद अब्दुल हमीद ने प्रदान किया।

श्री मोदी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर भी गए और वहां पूजा-अर्चना की। उसके बाद वह गोपीबाग स्थित रामकृष्ण मठ गए। उन्होंने बारीधारा में भारतीय उच्चायोग की नई इमारत का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने छह परियोजनाएं भी लांच की। इन परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता भारत से मिली है। इसी दिन श्री मोदी ढाका में बांग्लादेश के उद्योग संघों के प्रमुखों से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्विटर पर कहा कि मोदी प्रमुख उद्योग संघों के प्रमुखों से मिले। गौरतलब है कि मोदी ने आगमन के बाद राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा कर उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष में बलिदान दिया था। भारतीय प्रधानमंत्री ने इसके बाद बंगबंधु स्मारक संग्रहालय का दौरा किया और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की।

क्या है सीमा समझौता

भारत और बांग्लादेश के बीच 41 साल पुराना विवाद, जो इस ऐतिहासिक समझोते के बाद समाप्त हुआ। इस भू-सीमा समझौते के तहत भारत बांग्लादेश को 111 कॉलोनी अथवा परिक्षेत्र सौंपेगा। इन कॉलोनियों की कुल

जमीन 17,160.63 एकड़ है। वहीं बांग्लादेश 51 कॉलोनी अथवा परिक्षेत्र सौंपेगा। इन कॉलोनियों की कुल जमीन 7,110.02 एकड़ है। इसके अलावा 6.1 किलोमीटर अनिश्चित सीमा का भी सीमांकन किया जाएगा।

भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि-सीमा समझौता 16 मई, 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान के बीच हुआ था। बांग्लादेश की संसद 'जातीय संसद' ने इसे तत्काल मंजूरी दे दी थी।

भूमि समझौते के संधि पत्र पर दोनों पक्षों ने छह सितंबर, 2011 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में जिन चार राज्यों की भूमि अदला-बदली की जाएगी, उनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

बांग्लादेश में 111 भारतीय कॉलोनियों में कुरीग्राम जिले में 12, नीलफामरी में 59 और पन्हागर में 36 शामिल हैं। भारतीय कॉलोनियों में करीब 37 हजार लोग रहते हैं, वहीं बांग्लादेशी कॉलोनियों में 14 हजार लोग रहते हैं। समझौते के मुताबिक इन कॉलोनियों के लोगों को नागरिकता चुनने का विकल्प होगा। वे चाहें तो दोनों में से किसी एक देश की नागरिकता ले सकते हैं।

दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा का निपटारा पहले ही हो चुका है। द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सात जुलाई, 2014 को दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा की रूपरेखा पेश की थी।

भारत और बांग्लादेश ने 22 प्रमुख समझौतों पर किये हस्ताक्षर

- मानव तस्करी एवं जाली नोटों की तस्करी पर अंकुश लगाने तथा एक भारतीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने सहित 22 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर।
- 1974 के भूमि सीमा समझौते की पुष्टि और 2011 के प्रोटोकॉल, 1974 के भूमि सीमा समझौते के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों पर पत्रों के आदान-प्रदान तथा नए सिरे से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर हस्ताक्षर।
- ढाका से होते हुए कोलकाता से अगरतला जाने वाली बस सेवा सहित दो प्रमुख बस सेवाओं पर समझौते हुए हैं जिनसे यात्रियों को सहूलियत होगी। ढाका के रास्ते अगरतला की बस सेवा से यात्रियों की यात्रा के समय में करीब एक तिहाई की बचत होगी।
- दूसरा मार्ग ढाका-शिलांग-गुवाहाटी का होगा। इस बस सेवा को तीनों नेताओं ने हरी झंडी दिखाई। मानव तस्करी की रोकथाम, जाली नोटों के प्रसार एवं तस्करी को रोकने तथा भारतीय आर्थिक क्षेत्र की स्थापना को लेकर दोनों पक्षों ने सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- बांग्लादेश को भारत की ओर से दो अरब डॉलर के कर्ज के संदर्भ में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- अन्य समझौतों में जल संधि और व्यापार तथा दोनों देशों के बीच तटीय पोत परिवहन के समझौता शामिल हैं।

प्रधानमंत्री का ढाका संबोधन

भारत बुद्ध की धरती, यहां पर कोई युद्ध नहीं हो सकता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दो दिवसीय बांग्लादेश दौरे के अंतिम दिन ढाका के बंगबंधु अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सेंटर में लोगों को संबोधित किया है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बांग्ला भाषा में संबोधन शुरू किया। मोदी ने कहा आज मेरी यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन लग रहा है, जैसे अभी यात्रा शुरू ही हो रही है।

उन्होंने कहा कि अगर एक वाक्य में मैं इन संबंधों का वर्णन करूं तो लोग सोचेंगे कि हम केवल पास-पास हैं, लेकिन अब दुनिया को यह भी स्वीकार करना होगा कि हम केवल पास-पास ही नहीं बल्कि साथ-साथ भी हैं। दोनों देशों द्वारा 6 जून को मंजूर किए भूमि सीमा समझौते पर श्री मोदी

ने कहा कि यह केवल भूमि का विवाद नहीं था जिसे सुलझा लिया गया है, बल्कि यह दिलों को जोड़ने वाला समझौता था।

उन्होंने कहा कि एक ओर जहां दुनिया में इलाकों पर कब्जे को लेकर लड़ाई होती है, भारत बुद्ध की धरती है यहां पर कोई युद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि भारत और बांग्लादेश ऐसे दो देश हैं जिन्होंने भूमि को घनिष्ठ रिश्तों की डोर बनाया है। उन्होंने एक समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख का भी हवाला दिया जिसमें एलबीए को बर्लिन की दीवार ढहाने के समान दिखाया गया था। महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता, शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में

स्थाई सदस्यता के लिए भारत का समर्थन और उसकी युवा आबादी आदि विभिन्न मुद्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि उनका दो दिवसीय दौरा समाप्त हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यात्रा (संबंधों के मामले में) अभी शुरू हुई है।

उन्होंने कहा कि मेरा बांग्लादेश के साथ भावनात्मक रिश्ता है। श्री मोदी ने अपना भाषण बांग्ला में शुरू करते हुए कहा कि केमो आछो, आमरा तोमके साथे निए चोलबो, आमार बांग्ला केमोन बोलतो (कैसे हैं आप, हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं, मेरी बांग्ला कैसी है।)

उन्होंने कहा कि उनका भव्य स्वागत वास्तव में 125 करोड़ भारतीयों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि वह विशेष रूप से खुश हैं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया।

श्री मोदी ने कहा कि वह बांग्लादेश की

ढाका में श्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें

- भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं, अब दुनिया को पता चलेगा कि दोनों देश साथ-साथ चलने वाले हैं। आज साथ-साथ चलने की बात कर रहे हैं तो आगे साथ-साथ दौड़ भी लगाएंगे।
- मेरी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का सपना एक ही है विकास। मैं भी सिर्फ विकास के बारे में सोचता हूं और यहां की प्रधानमंत्री भी विकास के बारे में ही सोचती हैं।
- बांग्लादेश के साथ मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मुक्ति आंदोलन के दौरान जितना खून बांग्लादेशियों को खौला, उतना ही भारतीयों के खून में भी उबाल आया।
- बांग्लादेश में बार-बार राजनीतिक संकट आए हैं, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश 6 फीसदी की विकास दर हासिल कर रहा है और यह कोई छोटी बात नहीं है।
- बिजली के लिए भारत-बांग्लादेश-भूटान-नेपाल मिलकर काम करें। भारत और बांग्लादेश सोलर एनर्जी के लिए आगे बढ़ेंगे।
- दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर देश भी आज अकेले नहीं चल सकता। इसलिए हमें दुनिया के सामने खुद को मजबूती के साथ पेश करना होगा।
- बांग्लादेश और सार्क देशों ने महिला सशक्तिकरण को नया आयाम दिया है। बांग्लादेश में उच्च पदों पर महिलाओं को देखकर खुशी होती है। इस मामले में हम दुनिया से कम नहीं।
- पंछी-पवन और पानी को वीजा नहीं लगता। पानी राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। तीस्ता के पानी का समाधान भी मानवीय मुद्दों के आधार पर होगा। तीस्ता के पानी के बंटवारे के लिए बातचीत जारी रहेगी।
- आतंकवाद की कोई जमीन नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं। भारत पिछले 40 सालों के इससे पीड़ित है। आतंकियों का कोई आदर्श नहीं, कोई मूल्य नहीं हैं। वे मानवता के खिलाफ हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए शेख हसीना के नीति का सम्मान करता हूं।
- हिन्दुस्तान ने जमीन के लिए कभी किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए यहां के लोगों के साथ अपना खून बहाया।

स्वतंत्रता के समर्थन में बुलाए गए सत्याग्रह में शामिल हुए थे। यह उनका पहला राजनीतिक प्रदर्शन था। बांग्लादेश में विकास की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के राज्यों को शिशु मृत्यु दर, पोषण, बालिकाओं, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बांग्लादेश की उपलब्धियों से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूरज पहले बांग्लादेश में उदित होता है उसके बाद भारत में, इसीलिए बांग्लादेश के विकास की किरणें भारत पर भी पड़ेंगी।

श्री मोदी ने कहा कि विकास का उनकी दूरदृष्टि और शेख हसीना की दूरदृष्टि पूरी तरह से मेल खाती है।

बांग्लादेशी मीडिया द्वारा व्यापक कवरेज मिली

बांग्लादेश की मुख्यधारा के मीडिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा को जबर्दस्त कवरेज दी है। इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में 'नये युग की शुरुआत' करार दिया गया है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बिकने वाले अखबार 'प्रोथम अलो' ने शीषर्क लगाया है, ''दि न्यू होराइजन इन रिलेशन्स'' (संबंधों में नया क्षितिज)। उसकी खबर में कहा गया है कि यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को नई उंचाइयों पर ले जाने के मकसद से 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।

एक अन्य अखबार 'समोकाल' ने शीर्ष लगाया, ''फ्रेंडशिप इन न्यू हाइट'' (दोस्ती की नई उंचाई)। अखबार ने मोदी की उस टिप्पणी को प्रमुखता से छापा है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के संस्थापक और मौजूदा प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अखबार ने कनेक्टिविटी बढाने के लिए हसीना की प्राथमिकताओं को भी जगह दी है।

प्रमुख अंग्रेजी दैनिक 'दि डेली स्टार' की हेडलाइन है, ''डान ऑफ ए न्यू एरा''। इसके उप-शीषर्क में लिखा है, ''हसीना, मोदी प्लेज म्यूचुअल ग्रोथ, लैंड डाक्यूमेंट एक्सचेंज्ड, 22 डील्स साइन्ड, 2 बिलियन यूएस डालर फ्रेश इंडियन क्रेडिट''। ये उप-शीषर्क परस्पर विकास, भूमि सीमा समझौते के दस्तावेजों के आदान प्रदान, 22 समझौतों, भारत द्वारा बांग्लादेश को दो अरब डालर कर्ज के ऐलान से जुड़े हैं।

न्यू एज ने एक लेख में कहा कि मोदी की बांग्लादेश यात्रा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण रही। व्यापार, आंतरिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव, निवेश तथा विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिहाज से यह यात्रा अहम है। ■

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~~

पृष्ठ 9 का शेष...

का विषय है, इसलिए हमने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया। सदियों से हमारी आस्था का केन्द्र जीवनदायिनी मां गंगा प्रदूषण-मुक्त हो इसलिए हमने 'नमामि गंगे' कार्यक्रम शुरू किया। हमारा इरादा है कि गांव की तस्वीर बदले और मूलभूत सुविधाएं जैसे प्रत्येक परिवार के लिए पक्का घर, चौबीस घंटे बिजली, पीने का शुद्ध पानी, शौचालय, सड़क और इंटरनेट की व्यवस्था हो जिससे लोगों का जीवनस्तर बेहतर हो। इन सबकी सफलता के लिए आपकी भागीदारी आवश्यक है।

हमने जोड़ने का काम किया है - देश की सीमाओं, बंदरगाहों और पूरे भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने के लिए सड़कें और रेलवे को नया जीवन देने का प्रयास। लोगों को जोड़ने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कनेक्टिविटी। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 'टीम इंडिया' की अवधारणा भी दूरियां मिटाने की कोशिश है। प्रथम वर्ष में विकास यात्रा की मजबूत नींव से देश ने खोया विश्वास पाया है। मुझे भरोसा है कि हमारे प्रयासों ने आपकी जिंदगी को छुआ होगा। यह मात्र शुरुआत है। देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आइये, हम सब संकल्प लें कि हमारा हर कदम देशहित में आगे बढ़े।

आपकी सेवा में समर्पित,

जय हिन्द!

नरेन्द्र मोदी
~~~~~~~~~~

विशेष साक्षात्कार

महासंपर्क अभियान के माध्यम से देश के सभी बूथों तक पहुंचेगी भाजपा : भूपेन्द्र यादव

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार भाजपा के प्रभारी तथा राज्यसभा सदस्य श्री भूपेन्द्र यादव अपनी कुशल संगठनात्मक क्षमता एवं बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में 'कमल संदेश' संपादक मंडल सदस्य श्री रामप्रसाद त्रिपाठी व श्री विकास आनन्द ने उनसे महासम्पर्क अभियान और बिहार के चुनाव पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने इस साक्षात्कार में महासम्पर्क अभियान की योजनाओं और आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव से सम्बन्धित संगठन की तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 'सात साल की जो थी रफ्तार, तीन साल में हुआ बंटाधार' को चुनाव का मुख्य नारा और 'विकास' को चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बनाकर प्रचार अभियान चलाया जायेगा। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश:-

- दस करोड़ से अधिक सदस्य भाजपा के बने हैं। अब इन सदस्यों से सम्पर्क किया जा रहा है। इस सम्पर्क का क्या उद्देश्य है?

महासम्पर्क अभियान के द्वारा जो पार्टी के नए सदस्य बने हैं उन सबको पार्टी की विचारधारा, इतिहास और कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराना है। और उन नए सदस्यों को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में लाकर शुभेच्छु से कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से अच्छा कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाना है।

दूसरा, हम चाहते हैं कि भाजपा का सब क्षेत्रों में विकास हो।

तीसरा, इसका यह भी लक्ष्य है राजनीतिक क्षेत्र में, पर्यावरण में रुचि रखने वाले, शिक्षा में रुचि रखने वाले, सामाजिक विषय में रुचि रखने वाले विभिन्न विषय में रुचि रखने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं के समूह को समाज के कल्याण के लिए लगाया जा सके तथा उनका डाटा तैयार किया जाए।

प्रत्येक मण्डल तक पार्टी का विकास करना, समाज के हरेक वर्ग तक पार्टी का विकास करना। पार्टी माने सर्वस्पर्शी पार्टी की जो हमारी अवधारणा है, इस अवधारणा में कितने आगे बढ़े, इसको संख्यात्मक, तथ्यात्मक रूप से जुटाना और सबसे बड़ी बात है सम्पर्क का कोई विकल्प नहीं है और सम्पर्क ही मानवीय सम्बन्धों का आधार है। पार्टी मानवीय सम्बन्धों, गुणों और मूल्यों को विकसित करे यह ही महासम्पर्क का उद्देश्य है।

- क्या आप को महासम्पर्क अभियान के दौरान नए बने सदस्यों की भारी संख्या तक पहुंचने में किसी समस्याओं का सामना करना पड़ा?

देखिए, पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मंडल स्तर तक बंटा है। और मण्डल स्तर से भी नीचे तक हमारे पास बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो बूथ स्तर तक सक्रिय रूप से काम करते हैं। भाजपा संगठन देश के सभी 9000 मण्डलों में समुचित रूप से कार्य करता है। अत: हमारे मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क के कारण महासम्पर्क अभियान पूर्ण सफलता की तरफ अग्रसर है। किन्तु सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम देश के सभी बूथों तक पहुंच सके हैं। मेरा विचार है कि पार्टी महासम्पर्क अभियान के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है।

- पार्टी के विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 लाख सक्रिय सदस्यों को प्रशिक्षित करने का भी उद्देश्य है। इस भारी उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो सकेगी और

आपका इस बारे में रोडमैप क्या है?

हां, लगभग 15 लाख सक्रिय सदस्यों को 'प्रशिक्षण' मिलेगा। इसके लिए हमने तीन स्तरीय व्यवस्था में 'शुभेच्छु' से सदस्य और सदस्य से पार्टी का 'कार्यकर्ता' बनाने का लक्ष्य रखा है। इसकी प्राप्ति के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कार्यक्रम का एक ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार किया है। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि कुछ सदस्य भाजपा के पुराने कार्यकर्ता है और कुछ सदस्य अत्यंत शिक्षित (योग्य) हैं और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में योग्यता रखते हैं, जैसे डाक्टर, वकील, शिक्षक, किसान, विद्यार्थी, कार्पोरेट कर्मचारी, और महिलाएं आदि जिनमें से 15 लाख सक्रिय सदस्य चुने जाएंगे। उनका उपयोग करने के लिए समाज और देश के लिए उनकी ऊर्जा का उपयोग तथा प्रशिक्षित करने का काम किया जाए। और मुझे विश्वास है कि वे भविष्य में पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे।

– क्या आप महासम्पर्क अभियान के संगठनात्मक ढांचे के बारे में विस्तार से बता सकते हैं?

हमने महासम्पर्क अभियान के लिए तीन स्तरीय ढांचा तैयार किया है। जो मण्डल स्तर से, जिला स्तर और राज्य स्तर तक फैला है। राज्य स्तर पर हम पहले ही सदस्यता के डाटा को स्टोर कर चुके हैं जो हमने डिजीटल फार्म में व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान संग्रहीत किया था। अब सभी राज्यों ने जिला स्तर पर डिजीटल टीमें बना ली हैं और जिलों में महासम्पर्क अभियान का फार्मेटेड किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार, मण्डल स्तरीय कार्यकर्ता इस फार्मेट को बूथ स्तर तक ले जाएंगे और विभिन्न बूथों पर इन्हें वितरित किया जाएगा और 'मिस कॉल' के जरिए नए सदस्यों की सदस्यता की पुष्टि की जाएगी। प्रत्येक नए सदस्य के मोबाइल की 'मिस्ड कॉलों' को देकर और सदस्यता के फार्म पेश कर इन सदस्यों की पुष्टि की जाएगी। हमने यह विधि वैज्ञानिक ढंग से तैयार की है और बिना किसी बाधा के दो दिनों में इसे सुनिश्चित किया जा सकेगा।

– महासम्पर्क अभियान की सफलता के लिए केन्द्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं?

राष्ट्रीय स्तर पर हमने दो कार्यशालाएं और डिजिटल टीम के लिए एक वर्कशाप आयोजित की है। हमने एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की है। महासम्पर्क अभियान के लिए सभी प्रदेशों में उनका डाटा पहुंच गया है। सभी प्रदेशों में अपनी डिजीटल कार्यशाला पूरी हो गई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्र, पार्टी का साहित्य तथा केन्द्रीय सरकार की उपलब्धियां पहले ही जिला स्तर तक भेजी जा चुकी हैं। मणिपुर, लक्षद्वीप और सिक्किम जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर, जहां समीक्षा बैठकें नहीं हो सकीं, अन्य सभी राज्यों में यह काम पूरा हो चुका है तथा महासम्पर्क अभियान सुचारू रूप से चल रहा है।

– हाल ही में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन भाजपा मुख्यालय में हुआ। इसका उद्देश्य और संदेश क्या था?

यह प्रदेश को समझने के लिए हुई कि क्या राज्यों में संगठनात्मक ढांचा ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं तथा पूर्ण समग्रता में महासम्पर्क अभियान के कार्यक्रम की समीक्षा की गई। यह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में रखी गई थी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम को मंडल स्तर तक जारी रखने का निर्देश दिया और मुझे विश्वास है कि इससे हमारे कार्यकर्ताओं को सफलता मिलेगी जिससे वे निर्धारित अवधि के अंदर महासम्पर्क अभियान को पूरा कर सकेंगे।

– बिहार के प्रभारी के रूप में आप जानते ही है कि राज्य में एनडीए की पिछली सरकार में भाजपा मंत्रियों ने अच्छे ढंग से कार्य किया और उन्होंने अपने-अपने विभागों का काम कहीं अधिक कुशलता से किया था। क्या भाजपा इसको लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रही है?

बिहार के लोग इस तथ्य को जानते हैं और वे जानते हैं कि जेडी(यू) भाजपा सरकार के सात वर्षो के शासन काल में क्या हुआ जिसे जेडी(यू) सरकार के पिछले तीन वर्षों के शासन में तबाह कर दिया। जेडी(यू)-भाजपा गठबंधन सरकार के शासन युग में एक मुख्यमंत्री था और सरकार की शासन व्यवस्था

अच्छी थी। अब पिछले तीन वर्षों में जेडी(यू) सरकार में तीन मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और राज्य के शासन गठबंधन में नितांत भ्रम ही भ्रम फैला हुआ। आज तो ऐसा लगता है कि बिहार में 'गवर्नमेंट आफ कंफ्यूजन' यर्थात भ्रम वाली सरकार का राज्य चल रहा है।

जेडी(यू) में विलय के बाद नीतीश कुमार भी यह नहीं बता सकते हैं कि बिहार में किस पार्टी का शासन है। उसका पार्टी 'सिम्बल' क्या है और उसका झण्डा क्या है? अत: भाजपा ने नारा दिया है- 'सात साल की जो थी रफ्तार, तीन साल में हुआ बंटाधार'। न तो भाजपा और न ही बिहार के लोग लालू के जंगल राज को दोहराने देंगे ना नीतीश कुमार को फिर से 'गवर्नमेंट आफ कंफ्यूजन' को वापस आने देंगे।

– अन्य घोटाले के अलावा, हाल ही में बिहार में 3000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला सामने आया है। क्या आप चुनाव प्रचार के दौरान इन भ्रष्टाचारों को लोगों के सामने लाने की योजना बना रहे हैं?

यह सच है कि जेडी(यू) सरकार के शासन काल में बिहार में चावल घोटाला हुआ। आजकल बिहार के शासन के क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नि:संदेह हम इन मुद्दों को पूरी तरह से उठाएंगे। किन्तु, हमारा प्रमुख ध्यान सुशासन और विकास पर रहेगा।

बिहार पहले भी कई अवसरों पर भाजपा में अपना विश्वास प्रगट कर चुका है, और विशेषकर पिछले लोग सभा चुनावों में भाजपा को लोगों का भारी समर्थन मिला था। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी पार्टी को चुनावों में भारी विजय मिलेगी, जिससे बिहार को नया बिहार बनाया जा सके ताकि वहां सुशासन का बोलबाला हो।

– अभी जेडी(यू), आरजेडी और कांग्रेस का अवसरवादी गठबंधन बन रहा है। क्या आपको नहीं लगता की इनका 'सामाजिक समीकरण' विकास पर भारी पड़ेगा या 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह 'विकास' भारी पड़ेगा?

हमारा मानना है कि सामाजिक न्याय की परिभाषा को नए तरीके से बिहार के इस चुनाव में बताया जाए। सामाजिक न्याय का मतलब यह नहीं है कि कुछ जातियों को अपने अधीन बनाकर उनका अधिपति बनकर उनका शोषण किया जाए। और उनका केवल उपयोग अपने और अपने परिवार की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किया जाए। हमारा सामाजिक न्याय का अर्थ यह है 'सबका साथ, सबका विकास'। इसमें भारतीय जनता पार्टी सभी की भागीदारी से चुनाव लड़ेगी और सबके लिए करेगी। केवल और केवल कुर्सी के लिए गठबंधन नहीं करेगी।

– विकास के अलावा अन्य कौन से मुद्दे हैं जिन पर भाजपा आगामी बिहार चुनावों में विशेष ध्यान रहेगा?

पिछले तीन वर्षों में बिहार में जेडी(यू) शासन ने बिहार को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहां भ्रष्टाचार तीव्र गति से चल रहा, विकास पूरी तरह ठप्प है और लोगों को अपनी आजीविका के लिए देश के विभिन्न भागों में जाना पड़ता है और वे गुस्से में हैं। अत: भाजपा राज्य में कहीं अधिक तेजी से विकास करने पर विशेष ध्यान देगी। इस समय केन्द्र में भाजपा सरकार है और यदि भाजपा बिहार में सत्ता में आती है तो वह केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिल कर राज्य में विकास का कार्य मिल कर करेंगे।

हम सुनिश्चित करेंगे कि समाज के सभी वर्गों के लिए विकास के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए। हम सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा मिले और अंतत: हम राज्य के लोगों में विश्वास का वातावरण पैदा करेंगे।

– पिछले कुछ महीनों में आपने बिहार का व्यापक दौरा किया है। क्या आप समझते हैं कि संगठन आगामी विधानसभा चुनावों में राजनैतिक विरोधियों का सामना करने को तैयार है?

नि:संदेह, बिहार में पार्टी का हर स्तर पर अच्छा संगठन है। हमारी वहां नेतृत्व की अच्छी श्रृंखला है, वहां अनेक सांसद, केन्द्र सरकार के मंत्री और वहां 'टीम बिहार' के अनेक विशेष बिन्दु हैं, जो चुनावों में लड़ेंगे और सभी मिल कर बड़े जोर-शोर से काम कर रहे हैं जिनसे पार्टी की विजय सुनिश्चित है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं भाजपा बिहार के आगामी चुनावों में भारी बहुमत से जीत कर सामने आएगी। ■

श्रद्धांजलि : 23 जून बलिदान दिवस पर विशेष

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी : एक आदर्श नेता

पं. दीनदयाल उपाध्याय

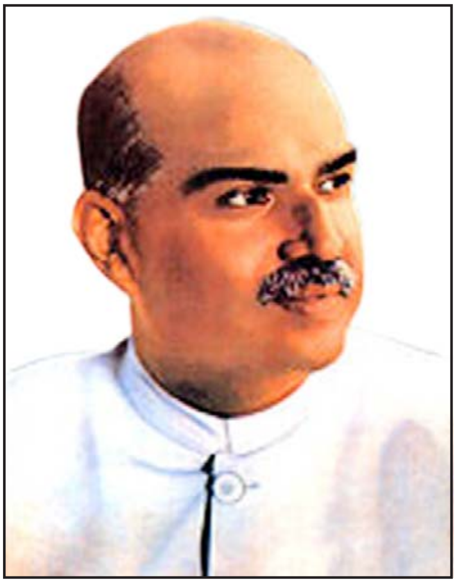

बंगाल के बाहर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के अधिकांश भाषण हिन्दी में होते थे। जब वह पहली बार हिन्दू महासभा के अधिवेशन में उपस्थित हुए तो वह हिन्दी में बोल नहीं सके। परन्तु उन्होंने वायदा किया कि वह जल्द इस भाषा को सीख लेंगे और अगले वर्ष उन्होंने हिन्दी में भाषण दिया। निःसन्देह उनसे हिन्दी में सही व्याकरण के उपयोग करने की आशा नहीं की जा सकती थी। परन्तु उन्होंने अपने आप को सही ढंग से अभिव्यक्त किया और अधिकांश अवसरों पर उनकी भाषा अत्यंत शक्तिशाली होती थी।

जब उन्होंने हिन्दी पर आग्रह किया

उन्होंने भारतीय जनसंघ के उद्घाटन सत्र का अध्यक्षीय भाषण अंग्रेजी में लिखा। परन्तु वह प्रतिनिधियों को इसकी प्रतियां हिन्दी में वितरित करना चाहते थे। परन्तु समय बहुत कम था। यह 20 अक्टूबर का दिन था। भाषण अगले दिन प्रातः 10 बजे पढ़ा जाना था। इसके अलावा विषय समिति की बैठक भी 26 तारीख को होनी थी। परन्तु, वह इस विषय पर बहुत उत्सुक थे। फलस्वरूप, न केवल अध्यक्षीय भाषण, बल्कि घोषणा-पत्र को भी हिन्दी में अनूदित किया और अर्जुन प्रेस के कर्मचारियों की अपार उत्साह के कारण दोनों को समय पर छाप कर प्रतिनिधियों को पेश किया गया। किन्तु, डा. मुकर्जी जी ने भाषण नहीं पढ़ा। जैसा कि रिवायत थी, उसके अनुसार उनका मुंह-जबानी भाषण अनुदित भाषण से कहीं अधिक प्रभावशाली था।

जब वह पहली बार हिन्दू महासभा के अधिवेशन में उपस्थित हुए तो वह हिन्दी में बोल नहीं सके। परन्तु उन्होंने वायदा किया कि वह जल्द इस भाषा को सीख लेंगे और अगले वर्ष उन्होंने हिन्दी में भाषण दिया। निःसन्देह उनसे हिन्दी में सही व्याकरण के उपयोग करने की आशा नहीं की जा सकती थी। परन्तु उन्होंने अपने आप को सही ढंग से अभिव्यक्त किया और अधिकांश अवसरों पर उनकी भाषा अत्यंत शक्तिशाली होती थी।

उन्होंने 'सर्वनाश' की बजाय 'खतरनाश' को बेहतर समझा

हिन्दी भाषणों में डॉ. मुकर्जी ने संस्कृत शब्दों का उपयोग किया। अतः उन्हें कभी भी सही शब्द चुनने में कठिनाई नहीं आई। उनकी संस्कृत शैली के कारण उनकी भाषा एक दम शुद्ध थी। किन्तु, उन्होंने 'सर्वनाश' शब्द का उपयोग नहीं किया, बल्कि 'खतरनाश' कहना बेहतर समझा। यह वह शब्द था, जिसे उन्होंने स्वयं गढ़ा था। वह हमेशा सोचा करते थे कि वह गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। परन्तु, वह गलती बताने में हिचकिचाहट महसूस करते थे। एक दिन, निःसंदेह, जब आम बातचीत चल रही थी तो भाषा बहस का विषय बन गया तो मैंने 'खतरनाश' शब्द को सही शब्द नहीं बताया। सही होता, अगर वह 'सर्वनाश' या 'सत्यानाश' का प्रयोग करते। उन्होंने इस सुझाव के लिए मुझे धन्यवाद दिया, परन्तु कहा कि ''क्या तुम्हें महसूस नहीं होता है कि 'खतरनाश' और 'सर्वनाश' या 'सत्यानाश' का प्रयोग करते। उन्होंने इस सुझाव के लिए मुझे धन्यवाद दिया, परन्तु कहा कि ''क्या तुम्हें महसूस नहीं होता है कि 'खतरनाश' और 'सर्वनाश' के बीच दो शब्दों के अंतर की छाया है? हां, अन्तर तो है।

यहीं वह अन्तर था जिससे डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी देश के अनेक विरोधी नेताओं से अलग-थलग दिखाई

पड़ते थे। डॉ. मुकर्जी सतर्क थे और हमेशा ही सरकार और दिग्गजों का ध्यान गलत नीतियों का कदमों की ओर दिलाया करते थे। परन्तु वह न तो तबाही के पैगम्बर थे, न ही 'साईनिक' (पागल) थे। अतः उन्होंने जानबूझकर 'खतरनाश', 'सर्वनाश' शब्द चुने जिनका मतलब पूर्ण 'तबाही' से था, जो फारसी और संस्कृत के मिले-जुले शब्दों से निकलता था। यदि इस अन्तर को समझ लिया जाए और इस विरोध के अन्तर को मान लिया जाए तो सरकार का बेकार की आलोचना नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में रचनात्मक योगदान मिल पाएगा। किसी शब्द के विरोध काम गुमराह करना नहीं होता है, बल्कि नेतृत्व करना बन जाता है। कामकाज नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक होना चाहिए। इससे सरकार को कभी आलसी या लापरवाह नहीं बनने देना चाहिए। परन्तु इससे लोगों में भय भी पैदा नहीं होना चाहिए और न ही मनोबल गिरना चाहिए।

आज हमारे पास कोई मुकर्जी नहीं है। परन्तु उनकी स्प्रिट जिंदा है। यदि कोई आप से देश के अंधकारमय भविष्य की बात करता है तो उसे नकार दो। हम केवल दूर से देखने वाले लोग नहीं है, बल्कि देश के इतिहास को बनाने के लिए पूर्ण सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोग हैं। यदि जो लोग सत्ता में बैठे हैं और वे गलती करते हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि उन्हें सुधारें, केवल उनकी गलतियों की तरफ इशारा कर संतोष से न बैठ जाएं।

जनसंघ ने कभी अपना सिर झुकने नहीं दिया

प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने पूरी सीटें अपने पक्ष में कर लीं। अधिकांश विरोधी नेता हार गए। ऐसी पार्टियां जिन्होंने वायदा किया था कि वे सरकार परिवर्तन पर देश की तस्वीर बदल देंगे, हार गई। ऐसे वातावरण में एक व्यक्ति डा. मुकर्जी के पास पहुंचा और कहा कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय है। डॉ. मुकर्जी ने उससे दो प्रश्न पूछे। 1. क्या तुम्हारा लोकतंत्र में विश्वास है?, 2. क्या तुम सक्रिय रूप से राजनीति में कार्य करने का संकल्प करते हो। उस सज्जन ने 'हां' में जवाब दिया। इस पर डॉ. मुकर्जी ने कहा तो अब बताओं, कैसे लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय हो सकता है और यह भी जोड़ा कि यह तभी अंधकारमय होगा यदि हम काम न करें या आपको विश्वास ही न हो। जहां विश्वास रहता है, वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। यह उज्ज्वल ही होगा।''

मैंने देखा कि वास्तव में यही वह व्यक्ति है जो नेतृत्व कर सकता है। हम कभी-कभी लोगों से मिलते हैं, जिन्हें ''नेता'' कहा जाता है परन्तु, शायद ही वे लोगों में विश्वास पैदा कर सकते हों। इसके विपरीत यदि आप उनके पास पूर्ण विश्वास के साथ पहुंचे तो आप आत्मसंतोषहीनता लेकर लौटें। डॉ. मुकर्जी उन लोगों में से ऐसे व्यक्ति नहीं थे। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने पराजय का रोना नहीं रोया। उन्होंने कहा कि यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जनसंघ ने कम से कम बेहतर कर दिखाया है। शेष सभी अन्य पार्टियों के सिर झुक गए परन्तु आपका अध्यक्ष सफल होकर आया है। हां, किसी भी निराशा तस्वीर की उज्ज्वल आयाम होता है और यही हमारे भविष्य को उज्ज्वलतर बनाने के लिए प्रेरित करता है।

समुद्री मीनार की प्रकाश शिखा

आज मुकर्जी की मृत्यु के 12 वर्ष बाद देश कठिन दौर से गुजर रहा है। आज हमारे पास कोई मुकर्जी नहीं है। परन्तु उनकी स्प्रिट जिंदा है। यदि कोई आप से देश के अंधकारमय भविष्य की बात करता है तो उसे नकार दो। हम केवल दूर से देखने वाले लोग नहीं है, बल्कि देश के इतिहास को बनाने के लिए पूर्ण सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोग हैं। यदि जो लोग सत्ता में बैठे हैं और वे गलती करते हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि उन्हें सुधारें, केवल उनकी गलतियों की तरफ इशारा कर संतोष से न बैठ जाएं। इसके साथ ही, यह भी हमारा काम है कि लोगों को एकजुट करें ताकि वे लोकतांत्रिक ढंग से उस सरकार को बदल दे जो उस सरकार सौंपे काम के बोझ को संभालने में असमर्थ रह जाती है। डॉ. मुकर्जी ने ही हमें यह रचनात्मक दृष्टिकोण दिया है। वह विरोधी पक्ष के नेता थे, जिनका उद्देश्य सत्ता में आना था।

यदि हम यह उद्देश्य निरन्तर अपने सामने रखें और अपने मिशन में विश्वास रखें तो विपक्ष सदैव जिम्मेदार बना रहेगा। हमारे लिए कोई रूकावट नहीं होगी, बल्कि इससे हमें देश में शासन चलाने की प्रेरणा मिलेगी। हमारा रवैय्या ही केवल लोकतंत्र का सफल बनाएगा और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करेगा।■

(साभार : आर्गेनाइजर 4 जुलाई 1965)

'वन रैंक, वन पेंशन' जरूर लागू होगा : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार 'वन-रैंक-वन पेंशन' (ओआरओपी) के उलझे हुए मसले का जल्द ही हल निकालेगी और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों का हित उनके लिए विश्वास और देशभक्ति का मसला है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व सैन्यकर्मियों का हित मेरे लिए विश्वास और देशभक्ति का मसला है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान कहा कि उनकी सरकार ओआरओपी मसले का हल जरूर निकालेगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं। 40 सालों से ओआरओपी एक सवाल है और अब तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। श्री मोदी ने ओआरओपी के मुद्दे को जटिल और 40 सालों से लंबित बताते हुए कहा कि सरकार के संबंधित अधिकारी इस मुद्दे का हल निकालने में जुटे हैं। उन्होंने पूर्व सैन्यकर्मियों से मुद्दे को लेकर राजनीतिक रुख नहीं अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह सरकार 'वन रैंक, वन पेंशन' का जल्द ही समाधान निकालेगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मैं सभी सैनिकों से अनुग्रह करता हूं कि जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वे पिछले 40 सालों से आपके साथ खेल रहे हैं। मैं ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहता, जिससे यह मुद्दा अधिक जटिल बन जाए। मुझे कुछ समय और दीजिए। आपने 40 साल तक इंतजार किया है, मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। मुझे इस समस्या का समाधान निकालने का अवसर दीजिए।

श्री मोदी ने कहा कि 20 दिनों में ही 8.52 करोड़ लोग इस परियोजना से जुड़े। यह जनता के लिए केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक उत्थान के लिए शुरू की जा रही पहलों पर उनके भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना देश में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।

'मन की बात' में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर संतोष जताया। उन्होंने यह भी कहा कि वह देश में गरीबी के खिलाफ गरीबों की फौज खड़ी करना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि 20 दिनों में ही 8.52 करोड़ लोग इस परियोजना से जुड़े। यह जनता के लिए केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक उत्थान के लिए शुरू की जा रही पहलों पर उनके भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना देश में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले एक रुपया प्रतिमाह पर सुरक्षा योजनाएं शुरू करना सोच से परे बात थी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को आत्मनिर्भर और सशक्त देखना चाहती है, ताकि उन्हें जीविका के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में योग विश्व को जोड़ने का एक उत्प्रेरक कारक बन गया है और यह 'वसुधैव कुटुंबकम' के परिदृश्य में भी बेहद प्रासंगिक है। श्री

मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में सफल बनाएं। उन्होंने विश्वकल्याण और मानवता के लिए योगदूत बनने और दुनिया के लिए योग की शिक्षा को सुलभ बनाने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू किए गए डीडी किसान चैनेल को किसानों के लिए खुला विश्वविद्यालय बताते हुए कहा कि यह कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हर शख्स के लिए हितकारी है। श्री मोदी ने किसानों और मछुआरों से पेशे को उन्नत बनाने के लिए डीडी किसान चैनल का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने मन की बात में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सफल छात्र-छात्राएं अपनी योग्यता के आधार पर भविष्य का पाठ्यक्रम चुनें। श्री मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जो विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस असफलता को नए विकल्पों की तलाश के अवसर के रूप में लें। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा हैं। हम असफलताओं से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ■

21 जून : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

योग में हिस्सा ले सकते हैं 100 देशों के लोग

योग भारत की शाश्वत व अमिट पहचान है। योग पर भारत को गर्व है। यह भारत द्वारा विश्व की दी गई एक अनुपम भेंट है। योग से तन और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है।

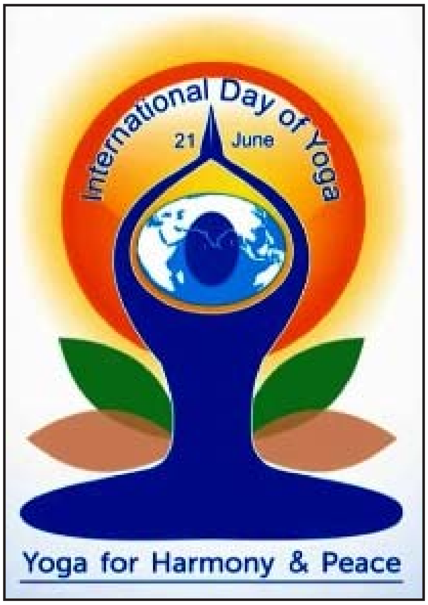

योग पर भारत क्यों न इतराए-इठलाए? योग हमारा ही है। यह भारत की पहचान है और अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी महत्ता को स्वीकार किया है तथा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया है। साथ यह भी बताते चलें कि यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि इस प्रथम आयोजन के मौके पर श्री मोदी ने खुद राजपथ पर सुबह योग करके इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। श्री मोदी खुद लंबे समय से योग करते रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि राजपथ पर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 45 हजार से अधिक लोगों एक साथ योग करेंगे। इसके अलावा करीब 100 देशों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री सहित मशहूर योग गुरु और अपने अपने क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां भी हिस्सा लेंगी। सरकार का उद्देश्य एक ही स्थान पर अधिकतम संख्या में एक साथ लोगों के योग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है। योग का आयोजन राजपथ पर सुबह सात बजे शुरू होगा और 7 बजकर 35 मिनट तक चलेगा। दिल्ली के अलावा, हर राज्य की राजधानी में भी इसी तरह के योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दुनिया के 190 देशों में स्थित भारतीय दूतावास भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं।

श्री मोदी ने ट्वीट के जरिये बताए योग आसनों के गुर

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के विभिन्न आसनों के बारे में ट्वीट के जरिये जानकारी देनी शुरू की है।

इस क्रम में अपने पहले ट्वीट में मोदी ने कहा, 'न्यूरोमस्कुलर समन्वय और संतुलन को बेहतर बनाने और स्नायु को जीवंत करने के लिए वृक्षासन करें।' उन्होंने साथ में एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें वृक्षासन करते दिखाया गया है।

इससे पहले 3 जून को उन्होंने ट्वीट के जरिये जानकारी दी थी कि आज से वह प्रतिदिन योग आसनों के बारे में जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि योग आसन शरीर और मन में स्थिरता लाने में सक्षम हैं। ■

सरकार की उपलब्धियां : शिलांग (मेघालय)

उत्तर-पूर्व क्षेत्र मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में : जितेंद्र सिंह

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 26 मई को शिलांग में मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी 'साल एक, शुरुआत अनेक' का उद्घाटन किया। मोदी सरकार के एक वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर उत्तर पूर्व क्षेत्र के अपने तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन डॉ. सिंह ने मेघालय के मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा के साथ बैठक की और शिलांग में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया।

मेघालय के मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल शर्मा के साथ बैठक के दौरान डॉ. सिंह ने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है और यह प्रधानमंत्री के "इंडिया विजन" का अहम भाग है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व का प्रमुख केंद्र होने के बावजूद शिलाग का दिल्ली से सीधा वायु संपर्क नहीं है। डॉ. सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वह इस विषय को नागर विमानन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू के समक्ष उठायेंगे। श्री सिंह ने कहा कि 15 अप्रैल से दिल्ली से दीमापुर से एक सीधी दैनिक विमान सेवा की शुरुआत हुई है और दिल्ली से आइजोल के लिए साप्ताहिक या सप्ताह में दो बार सेवा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे है।

बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि जैविक खेती के लिए विचार पत्र विभिन्न मंत्रालयों के बीच पहले ही वितरित किया जा चुका है और इसे कैबिनेट के समक्ष जल्द से जल्द लाने के प्रयास किए जाएंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी के "मेक इन इंडिया" योजना के अंतर्गत "मेक इन नॉर्थ ईस्ट" मिशन का महत्वपूर्ण भाग है। मोदी सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि यह सरकार के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास की परिकल्पना को सही रूप से प्रदर्शित करता है और यह इस बात को दोहराता है कि यह उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास और प्रगति करने का सर्वोत्तम समय है क्योंकि इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का समर्थन और सहयोग प्राप्त है।

एक अन्य कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि हममें से यह हर एक की जिम्मेदारी है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के दूत बनकर देश के हर कोने में जाएं और लोगों को सरकार द्वारा निर्धनों और किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं के संबंध में जागरूक करें। सरकार द्वारा शुरू किए गए कौशल विकास योजनाओं से उत्तर पूर्व के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और बीमा और पेंशन से संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी। ■